**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2930**

**08 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ**

**इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन**

**2930. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) देश भर में कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं; और

(ग) अगले पांच वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) :** इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना निजी या सार्वजनिक चार्ज पॉइंट ऑपरेटरों (सीपीओ) द्वारा की जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के लिए नीतिगत ढांचा और आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण, बिक्री और अभिग्रहण के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय अपने इलेक्ट्रिक (एवं हाइब्रिड) वाहनों के द्रुतगामी अभिग्रहण और विनिर्माण (एफएएमई) स्कीम के तहत, सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करता है।

विद्युत मंत्रालय ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय भी किए हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से ईवी बैटरियों को चार्ज करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
(2) वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत के लिए एकल भाग टैरिफ लेना।
(3) वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर पीसीएस को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
(4) राजस्व साझाकरण मॉडल के माध्यम से पीसीएस के लिए प्रमोशनल दरों पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।
(5) प्रचालनरत पीसीएस के राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस के रूप में 'ईवी यात्रा' पोर्टल शुरू किया गया है।

**(ख) :** दिनांक 31 जुलाई, 2024 तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि देश भर में 25,202 ईवी पीसीएस संस्थापित किए जा चुके हैं।

**(ग) :** विद्युत मंत्रालय ने देश में पीसीएस की संस्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

*********